Toppersnotes®
Unleash the topper in you

RAS

राजस्थान प्रशासनिक सेवा

राजस्थान लोक सेवा आयोग

भाग - 7

भारत की अर्थव्यवस्था

SIERRA
INNOVATIONS

RAS

भारत की अर्थव्यवस्था

क्र.सं.	अध्याय नाम	पृष्ठ सं.
1.	अर्थव्यवस्था के मूल सिद्धांत	1
2.	मुद्रा, मुद्रा आपूर्ति और मौद्रिक नीति	9
3.	मुद्रास्फीति	16
4.	वित्तीय मध्यस्थ	23
5.	वित्तीय बाजार	31
6.	बजट	36
7.	राजकोषीय नीति और कराधान	40
8.	सब्सिडी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS)	49
9.	बाह्य क्षेत्र और भुगतान संतुलन	54
10.	ई-कॉमर्स	61
11.	लेखांकन	65
12.	कृषि	70
13.	उद्योग	84
14.	सेवा क्षेत्र	95
15.	गरीबी	101
16.	सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण	112

3
CHAPTER
मुद्रास्फीति

पिछले वर्षों में पूछे गये प्रश्न

प्रश्न 1. मुद्रास्फीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: (2023)

कथन (A): हेडलाइन मुद्रास्फीति उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) संख्या में परिवर्तन की दर को संदर्भित करती है, जो एक सामान्य परिवार द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की एक मानक टोकरी की औसत कीमत का माप है।

कथन (B): कोर मुद्रास्फीति उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से कुछ अस्थिर कीमतों वाली वस्तुओं, जैसे कि खाद्य और ईंधन, को हटाने के बाद औसत उपभोक्ता कीमतों में परिवर्तन को मापती है।

इनमें से कौन सा सही है:

(1) न तो (A) और न ही (B) सही हैं।
(2) (A) और (B) दोनों सही हैं।
(3) केवल (B) सही है।
(4) केवल (A) सही है।
(5) प्रश्न का प्रयास नहीं किया।

प्रश्न 2. औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP), जो भारतीय अर्थव्यवस्था में औद्योगिक गतिविधियों का माप है, में क्या शामिल नहीं है? (2021)

(1) गैस और जल आपूर्ति
(2) बिजली
(3) निर्माण
(4) खनन

प्रश्न 3. **कथन (A):** लागत जनित मुद्रास्फीति कुल आपूर्ति वक्र में परिवर्तन के कारण होती है। (2018)

कारण (R): कुल आपूर्ति वक्र में बदलाव मजदूरी में वृद्धि के कारण होता है।

(1) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) का सही स्पष्टीकरण है।
(2) (A) और (R) दोनों सही हैं, लेकिन (R), (A) का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
(3) (A) सही है, लेकिन (R) गलत है।
(4) (A) गलत है, लेकिन (R) सही है।

प्रश्न 4. यदि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के आधार पर मुद्रास्फीति दर बढ़ती है, तो (2016)

(1) बैंक दर कम हो जाती है।
(2) रिवर्स रेपो दर कम हो जाती है।
(3) वैधानिक तरलता अनुपात (SLR) बढ़ जाता है।
(4) रेपो दर बढ़ जाती है।

विश्लेषण: यह अध्याय अवधारणाओं और तथ्यों दोनों को सम्मलित करता है, क्योंकि पिछले RPSC के प्रश्नों ने दोनों पहलुओं को शामिल किया है। इसलिए, यह अध्याय विस्तृत रूप से प्रस्तुत किया गया है ताकि अच्छी समझ सुनिश्चित हो सके।

मुद्रास्फीति

मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं की सामान्य कीमतें लगातार बढ़ती रहती हैं। इसके परिणामस्वरूप, मुद्रा की क्रय शक्ति में गिरावट होती है। मुद्रास्फीति एक व्यापक आर्थिक घटना है और इसका संबंध विशेष वस्तुओं या वस्तुओं के एक छोटे समूह की कीमत में वृद्धि से नहीं होता। मुद्रास्फीति से कीमत स्तर में बढ़ोत्तरी होती है परिणामस्वरूप आय के समान स्तर के बावजूद एक परिवार पहले की तुलना में कम मात्रा में वस्तुओं का उपभोग कर पाता है।

उदाहरण के लिए - एक परिवार की मासिक आय ₹100 है और वह एक वस्तु A खरीदता है जिसकी कीमत ₹4 है, जिससे उन्हें 25 इकाइयाँ खरीदने की अनुमति मिलती है। यदि वस्तु A की कीमत ₹5 तक बढ़ जाती है, तो वे उसी ₹100 के साथ केवल 20 इकाइयाँ खरीद सकते हैं। इससे पता चलता है कि मुद्रास्फीति उनकी क्रय शक्ति को कम कर देती है, जिसका अर्थ है कि वे समान धनराशि से कम खरीदारी कर सकते हैं।

मुद्रास्फीति के प्रकार

1. **मध्यम मुद्रास्फीति (Moderate Inflation)** - जब सामान्य कीमत स्तर धीरे-धीरे लेकिन निरंतर रूप से बढ़ता है, तो इसे मध्यम मुद्रास्फीति कहते हैं।
2. **तीव्र मुद्रास्फीति (Galloping Inflation)** - जब सामान्य कीमत स्तर में तेज़ी से और उच्च दर पर वृद्धि होती है तो इसे तीव्र मुद्रास्फीति कहते है। इसमें मुद्रास्फीति की दर दो अंकों या कभी-कभी तीन अंकों तक पहुँच जाती है। उदाहरण के लिए, 1970 के दशक में लैटिन अमेरिकी देशों में मुद्रास्फीति की दर 100 प्रतिशत से अधिक थी।
3. **अति-मुद्रास्फीति (Hyperinflation)** - जब मुद्रास्फीति की दर बहुत अधिक हो जाती है। उदाहरण के लिए, वर्ष 2008-09 के दौरान जिम्बाब्वे में कीमतें लगभग हर दिन दोगुनी हो गईं और और मुद्रा का कार्य जैसे 'मूल्य संग्रह' और 'विनिमय का माध्यम' के रूप में इसकी उपयोगिता समाप्त हो गई थी।
4. **रुद्ध मुद्रास्फीति (Stagflation)** - जब मुद्रास्फीति में बहुत धीरे या शून्य दर से वृद्धि होती है (स्थिर) लेकिन कीमतें बढ़ती रहती हैं। इस मुद्रास्फीति के दुष्प्रभावों में मुद्रास्फीति के साथ बेरोजगारी में वृद्धि शामिल है। यह 1970 के दशक में हुआ था, जब कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ीं और विकसित देशों में तीव्र मुद्रास्फीति उत्पन्न हुई।
5. **असमान मुद्रास्फीति (Skewflation)** - जब विभिन्न क्षेत्रों में कीमतें असमान रूप से बढ़ती हैं, जिससे कुछ क्षेत्रों में मुद्रास्फीति होती है जबकि अन्य क्षेत्रों में स्थिरता या गिरावट रहती है।
6. **अपस्फीति (Deflation)** - जब मूल्य स्तर में लगातार गिरावट होती है।

मूलभूत मुद्रास्फीति बनाम हेडलाइन मुद्रास्फीति

मूलभूत मुद्रास्फीति (Core Inflation)	हेडलाइन मुद्रास्फीति (Headline Inflation)
➢ इसमें भोजन और ऊर्जा जैसी वस्तुएं मुद्रास्फीति के आकलन में शामिल नहीं की जाती हैं क्योंकि इनकी कीमतें काफी अस्थिर होती हैं। ➢ उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI): इसका उपयोग मुद्रास्फीति को मापने के लिए सर्वाधिक रूप से होता है। यह दीर्घकालिक मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति का मापन करता है।	➢ इसमें भोजन और ऊर्जा (जैसे तेल और गैस) की कीमतें कुल मुद्रास्फीति के इस आकलन में शामिल होती हैं। जो अधिक अस्थिर और मुद्रास्फीति की वृद्धि के लिए प्रवण होती हैं। ➢ हेडलाइन मुद्रास्फीति किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक मुद्रास्फीति प्रवृत्ति को सटीक रूप से प्रतिबिंबित नहीं कर सकती।

मुद्रास्फीति के कारण

मांग-जनितमुद्रास्फीति	➢ ऐसे कारक जो कुल मांग में वृद्धि करते हैं जबकि समग्र आपूर्ति में कोई वृद्धि नहीं होती, मांग-जनित मुद्रास्फीति का कारण बन सकते हैं।	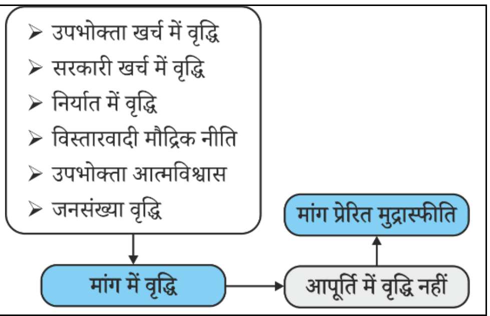 ➢ उपभोक्ता खर्च में वृद्धि ➢ सरकारी खर्च में वृद्धि ➢ निर्यात में वृद्धि ➢ विस्तारवादी मौद्रिक नीति ➢ उपभोक्ता आत्मविश्वास ➢ जनसंख्या वृद्धि मांग में वृद्धि आपूर्ति में वृद्धि नहीं मांग प्रेरित मुद्रास्फीति

लागत-प्रेरित मुद्रास्फीति	➢ श्रम, कच्चे माल, परिवहन और अन्य इनपुट लागत में वृद्धि, जो आपूर्ति पक्ष के कारक हैं, लागत-प्रेरित मुद्रास्फीति (Cost-push Inflation) का कारण बनती है। ➢ इसे मजदूरी प्रेरित मुद्रास्फीति (Wage-push Inflation) भी कहा जाता है क्योंकि उत्पादन की कुल लागत में मजदूरी का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ➢ उदाहरण के लिए, 1970 के दशक में तेल की कीमतों में तेजी, लागत-प्रेरित मुद्रास्फीति थी क्योंकि इससे उत्पादन लागत बढ़ गई थी।	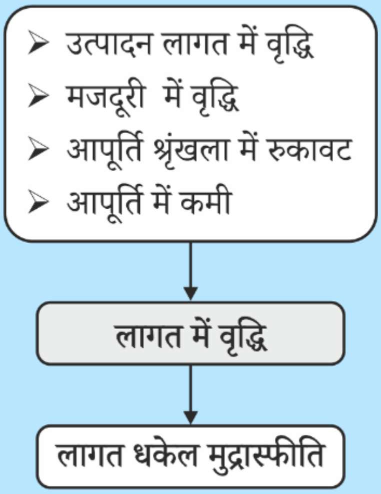 ➢ उत्पादन लागत में वृद्धि ➢ मजदूरी में वृद्धि ➢ आपूर्ति श्रृंखला में रुकावट ➢ आपूर्ति में कमी लागत में वृद्धि लागत धकेल मुद्रास्फीति
मौद्रिक मुद्रास्फीति	➢ किसी देश की मुद्रा आपूर्ति में लगातार वृद्धि के कारण उत्पन्न मुद्रास्फीति को मौद्रिक मुद्रास्फीति कहा जाता है। ➢ जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) अधिक मुद्रा जारी करता है (घाटे की वित्तपोषण), तो इससे मौद्रिक मुद्रास्फीति होती है।	
संरचनात्मक मुद्रास्फीति (बॉटलनेक मुद्रास्फीति)	➢ संरचनात्मक बाधाओं, जैसे संसाधन अंतर (जैसे कि बचत निवेश से कम होना), खाद्य की कमी (जो वर्षा आधारित कृषि से उत्पन्न होती है), विदेशी मुद्रा की कमी और कमजोर बुनियादी ढांचे के कारण होने वाली मुद्रास्फीति को संरचनात्मक मुद्रास्फीति (Structural Inflation) कहा जाता है। ➢ इस प्रकार की मुद्रास्फीति आमतौर पर विकासशील देशों में अधिक पाई जाती है।	
अंतर्निहित मुद्रास्फीति	➢ अंतर्निहित मुद्रास्फीति तब होती है जब लोग उम्मीद करते हैं कि कीमतें बढ़ती रहेंगी, जिससे वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि होती रहती है। यह आमतौर पर तब होता है जब मजदूरी बढ़ती है, और व्यवसाय इन बढ़ी हुई लागतों को ग्राहकों पर स्थानांतरित कर देते हैं, जिससे कीमतें और बढ़ जाती हैं।	

मुद्रास्फीति का मापन

मुद्रास्फीति को तीन स्तरों पर मापा जा सकता है – उत्पादक, थोक व्यापारी, और खुदरा व्यापारी (उपभोक्ता)। जब उपभोक्ता तक वस्तु पहुँचती है, तो सामान्यतः प्रत्येक स्तर पर उसकी कीमतों में वृद्धि होती है।

1. उत्पादक स्तर पर मापन: उत्पादक मूल्य सूचकांक (PPI)

- उत्पादक मूल्य सूचकांक (PPI) उत्पादक स्तर पर वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में समग्र परिवर्तन को दर्शाता है। (यह उत्पादन स्तर पर मुद्रास्फीति को मापता है)।
- भारत में अभी तक उत्पादक मूल्य सूचकांक का उपयोग नहीं हुआ है, लेकिन नीति आयोग ने इसे जल्दी ही लागू करने की योजना तैयार की है।

Toppersnotes Unleash the topper in you

2. थोक व्यापारी स्तर पर मापन: थोक मूल्य सूचकांक (Wholesale Price Index - WPI)

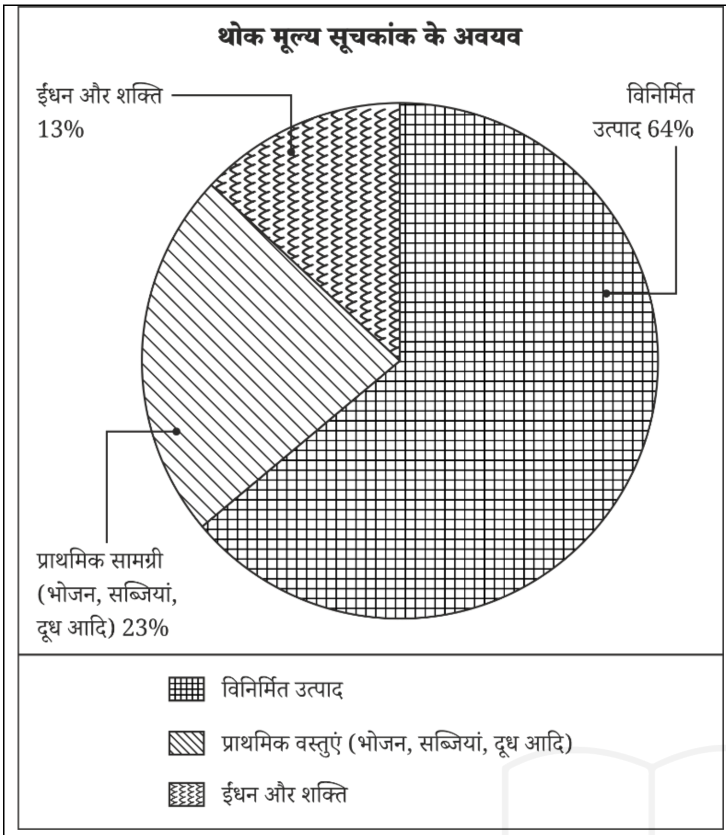

- WPI थोक वस्तुओं के एक प्रतिनिधि बास्केट की कीमत को दर्शाता है। यह सूचकांक सामान्य मूल्य स्तर में होने वाले बदलाव को दर्शाता है।
- WPI का वर्तमान आधार वर्ष 2011-12 है।
- यह केवल वस्तुओं को कवर करता है।
- विनिर्मित उत्पाद (64%) > प्राथमिक सामग्री (23%) > ईंधन और शक्ति (13%)।
    - ✓ इसे आर्थिक सलाहकार कार्यालय (OEA), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है।
- WPI बास्केट में कुल 697 वस्तुएँ शामिल हैं।

3. खुदरा/उपभोक्ता स्तर पर मापन: उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (Consumer Price Index - CPI)

- उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) खुदरा स्तर पर कीमतों में औसत बदलाव को मापता है।

$$\text{उपभोक्ता मूल्य सूचकांक} = \frac{\text{किसी निश्चित वर्ष में बाजार बास्केट की लागत}}{\text{आधार वर्ष में बाजार बास्केट की लागत}} \times 100\%$$

- इसे निर्वाह लागत सूचकांक (Cost of Living Index) भी कहा जाता है।
- यह उपभोक्ता स्तर पर मूल्य उतार-चढ़ाव को मापता है।
- इसका वर्तमान आधार वर्ष 2012 है।
- जब से RBI ने मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण की शुरुआत की है, तब से CPI (संशोधित) को भारत में मौद्रिक नीति के कार्यान्वयन के लिए एक मानक आधार के रूप में उपयोग किया जाता है।
- मौद्रिक नीति समिति के अनुसार, CPI (संशोधित) को 2% से 6% के बीच बनाए रखना आवश्यक है।
- यदि बैंक दर को कम किया जाता है तो CPI में वृद्धि होती है।

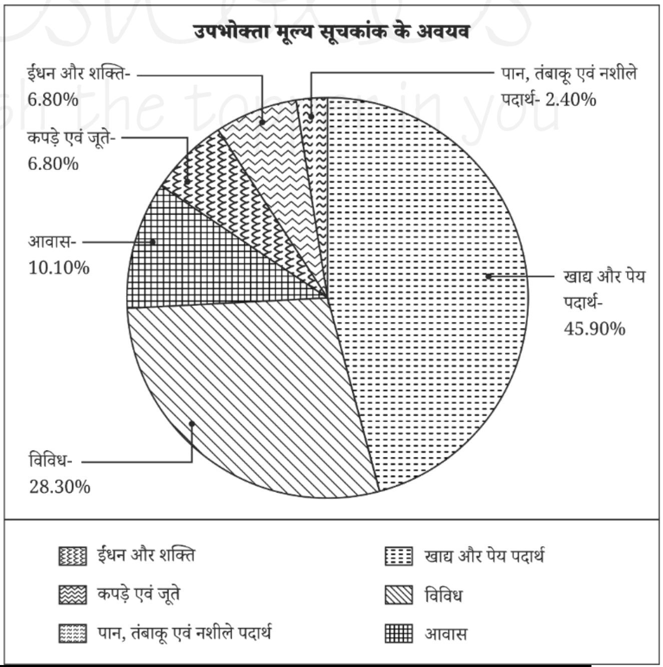

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के प्रकार-

CPI के प्रकार-	संकलन	आधार वर्ष
औद्योगिक श्रमिकों के लिये CPI (CPI-IW)	श्रम ब्यूरो, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	2016
कृषि श्रमिकों के लिये CPI (CPI-AL)	श्रम ब्यूरो, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	2012
ग्रामीण मज़दूरों के लिये CPI (CPI-RL)	श्रम ब्यूरो, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	2012
CPI (ग्रामीण/शहरी/संयुक्त)	NSO, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	2012

ToppersNotes Unleash the topper in you

अन्य सूचकांक

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (Index of Industrial Production - IIP)

- औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) विभिन्न क्षेत्रों में औद्योगिक उत्पादन में अल्पकालिक बदलावों को मापता है, जो किसी अर्थव्यवस्था की समग्र औद्योगिक प्रदर्शन को दर्शाता है।
- इसमें तीन मुख्य क्षेत्र शामिल हैं: खनन, विनिर्माण, और बिजली, जो औद्योगिक उत्पादन में उनके योगदान को प्रतिबिंबित करते हैं।
- यह नीति निर्माताओं, निवेशकों और विश्लेषकों के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक संकेतक है, जो औद्योगिक रुझानों के आधार पर निर्णय और नीति निर्माण में सहायता करता है।
- IIP का बढ़ना औद्योगिक विकास और मजबूत अर्थव्यवस्था को दर्शाता है, जबकि IIP में गिरावट आर्थिक मंदी या कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में चुनौतियों का संकेत देती है।
- इसे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा संकलित और प्रकाशित किया जाता है।
- इसका आधार वर्ष 2011-2012 है।

नोट- आठ कोर क्षेत्र: ये औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) में शामिल कुल वस्तुओं का 40.27% हिस्सा रखते हैं। भार के अनुसार आठ कोर क्षेत्र उद्योग(घटते क्रम में): रिफाइनरी उत्पाद > बिजली > इस्पात > कोयला > कच्चा तेल > प्राकृतिक गैस > सीमेंट > उर्वरक

मुद्रास्फीति के प्रभाव

1. **ऋणी और लेनदार**
   - ✓ जब कीमतें बढ़ती हैं, तो मुद्रा का मूल्य घट जाता है। यद्यपि देनदार (Debtors) उधार ली गई राशि को वापस कर देते हैं, परंतु मुद्रास्फीति के कारण उस राशि का वास्तविक मूल्य घट चुका होता है। इससे ऋण का बोझ कम हो जाता है और ऋणी को लाभ होता है।
   - ✓ दूसरी ओर, लेनदार (Creditors) को नुकसान होता है क्योंकि उन्हें वही राशि वापस मिलती है, लेकिन वास्तविक मूल्य कम हो चुका होता है।
2. **स्थिर आय समूह**
   - ✓ जिन लोगों की आय (जैसे वेतन) स्थिर होती है, वे मुद्रास्फीति के समय नुकसान में होते हैं क्योंकि वेतन में वृद्धि की गति मूल्य वृद्धि से धीमी होती है।
3. **व्यापारी और निवेशक**
   - ✓ उत्पादक और व्यापारी लाभ में होते हैं क्योंकि कीमतें बढ़ने के साथ ही उनकी इन्वेंट्री का मूल्य भी उसी अनुपात में बढ़ता है, जिससे उनकी बिक्री और लाभ दोनों में वृद्धि होती है।
   - ✓ भूमि संपत्ति के मालिक भी लाभ में होते हैं क्योंकि भूमि की कीमतें सामान्य मूल्य स्तर से तेजी से बढ़ती हैं।
4. **कृषक वर्ग**
   - ✓ भूमिपति (Landlords) को नुकसान होता है क्योंकि उन्हें स्थिर किराया प्राप्त होता है।
   - ✓ छोटे किसान, जो अपनी भूमि पर खेती करते हैं, लाभ में रहते हैं।
   - ✓ भूमिहीन कृषि श्रमिकों को भारी नुकसान होता है क्योंकि मुद्रास्फीति के कारण कृषि उत्पादों की कीमतें उत्पादन लागत (मजदूरी दर और भूमि राजस्व) से अधिक तेजी से बढ़ती हैं।

Toppersnotes Unleash the topper in you

5. **सरकार**
    - ✓ सरकार, एक ऋणी के रूप में, लाभ में रहती है क्योंकि उसके द्वारा जारी किए गए बॉन्ड पर ब्याज दरें स्थिर रहती हैं और मुद्रास्फीति की वजह से उनकी वास्तविक कीमत घट जाती है।
    - ✓ वहीं, घरेलू वर्ग करदाता के रूप में लाभ में रहता है क्योंकि मुद्रास्फीति के कारण देरी से चुकाए गए करों का वास्तविक मूल्य घट जाता है।

मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उपाय

मौद्रिक उपाय

- ➢ **केंद्रीय बैंक / RBI द्वारा अपनाए गए उपाय**
    1. बैंक दर में वृद्धि।
    2. मुक्त बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री।
    3. नकद आरक्षित अनुपात (CRR) और सांविधिक तरलता अनुपात (SLR) में वृद्धि।
    4. उपभोक्ता ऋण नियंत्रण।
    5. मार्जिन आवश्यकताओं में वृद्धि।
    6. रेपो दर और रिवर्स रेपो दर में वृद्धि।
- ➢ मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य कीमतों को स्थिर रखना है, यानी मुद्रास्फीति को 2% से 6% के लक्ष्य सीमा के भीतर बनाए रखना।

राजकोषीय उपाय

- ➢ सरकार द्वारा अपनाई गई राजकोषीय नीति:
    - ✓ सरकारी व्यय में कमी।
    - ✓ सार्वजनिक उधारी में कमी
    - ✓ कराधान में वृद्धि।

अन्य उपाय

- ➢ बफर स्टॉक्स का उपयोग, घरेलू आपूर्ति बढ़ाने के लिए आयात, निर्यात पर प्रतिबंध, प्रत्यक्ष मूल्य नियंत्रण, सट्टेबाजी और जमाखोरी पर प्रतिबंध, और वस्तु वायदा व्यापार पर रोक।
- ➢ प्रत्यक्ष कार्यवाही के माध्यम से मूल्य नियंत्रण
    - ✓ **दवा मूल्य नियंत्रण आदेश (DPCO):** यह प्रिस्क्रिप्शन की दवाओं की लागत को नियंत्रित करने का प्रयास करता है।
    - ✓ **आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955:** यह सरकार को किसी वस्तु को आवश्यक वस्तु के रूप में नामित करने की अनुमति देता है, ताकि वह उचित मूल्य पर जनता को उपलब्ध कराई जा सके।
- ➢ **सट्टेबाजी और जमाखोरी की जांच**
    - ✓ काला बाजारी रोकथाम और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति अधिनियम, 1980 के तहत, सरकार उन लोगों को हिरासत में ले सकती है जो मूल्य-हेराफेरी, भंडारण और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को कृत्रिम रूप से कम करने में लगे हुए हैं।
- ➢ **बफर स्टॉक्स नीति**
    - ✓ भारत सरकार अप्रत्याशित परिस्थितियों से निपटने के लिए खाद्यान्नों का बफर स्टॉक बनाए रखती है।
    - ✓ भारतीय खाद्य निगम (FCI) खाद्यान्नों और अन्य खाद्य पदार्थों की खरीद, भंडारण, परिवहन, वितरण और बिक्री का प्रभारी होता है।

- **निर्यात पर प्रतिबंध**
  - ✓ भारतीय सरकार घरेलू बाजार में कच्चे माल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम निर्यात मूल्य (MIP) निर्धारित करती है।
- **वस्तु वायदा व्यापार पर प्रतिबंध**
  - ✓ सट्टेबाजी से प्रेरित मूल्य वृद्धि दर से बचने के लिए सरकारें आमतौर पर भविष्य में वस्तुओं के व्यापार पर रोक लगाती हैं (जैसे- सरकार ने चना पर भविष्य के व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया)।

अध्याय से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली

- ✓ **अवस्फीति (Disinflation):** बिना किसी नकारात्मक प्रभाव के महंगाई को कम करने की प्रक्रिया को अवस्फीति कहते हैं।
- ✓ **प्रत्यवस्फीति (Reflation):** यह अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की प्रक्रिया है जिसमें धन की आपूर्ति बढ़ाना या करों को कम करना शामिल है।
- ✓ **फिलिप्स वक्र (Philips Curve):** इसमें बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के बीच एक विपरीत संबंध निर्धारित किया गया है। सिद्धांत के अनुसार, बेरोजगारी दर जितनी कम होती है, मुद्रास्फीति दर उतनी ही अधिक होती है और इसके विपरीत।

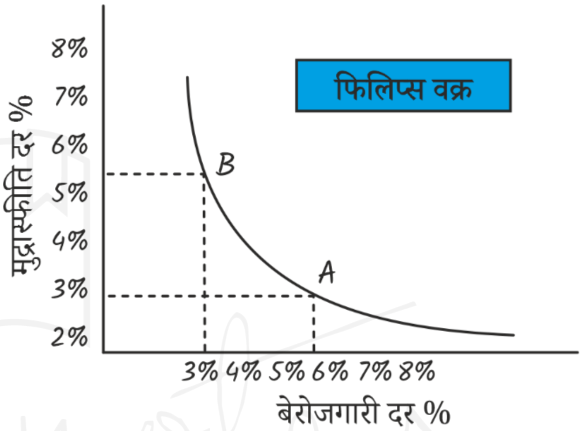

- ✓ **मुद्रास्फीति सर्पिल या मजदूरी-मूल्य सर्पिल:** यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब बढ़ती हुई मजदूरी दरें उत्पादन लागत बढ़ा देती हैं, जिससे व्यवसायों को कीमतें बढ़ानी पड़ती हैं। इसके परिणामस्वरूप मजदूरों द्वारा और अधिक मजदूरी की मांग की जाती है, जिससे महंगाई का एक सतत चक्र बन जाता है।
- ✓ **थालीनॉमिक्स:** भारतीय अर्थशास्त्री गुरचरण दास द्वारा दी गयी शब्दावली, जो भारतीय थाली (एक पारंपरिक भोजन थाली) की अर्थव्यवस्था का वर्णन करती है। यह इस बात का अध्ययन है कि भारत में भोजन की कीमतें और खपत का ढंग व्यापक आर्थिक स्थितियों को कैसे दर्शाते हैं।
- ✓ **मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारण (Inflation Targeting):** यह एक मौद्रिक नीति की रणनीति है जिसमें केंद्रीय बैंक एक निश्चित महंगाई दर को अपना लक्ष्य बनाता है और ब्याज दरों जैसे मौद्रिक उपकरणों को समायोजित करके उस लक्ष्य को प्राप्त करने और बनाए रखने का प्रयास करता है।

4
CHAPTER

वित्तीय मध्यस्थ

पिछले वर्षों में पूछे गये प्रश्न

प्रश्न 1. निम्नलिखित में से किस संस्थान ने हाल ही में एक केंद्रीकृत वेब पोर्टल 'UDGAM' लॉन्च किया है? (2023)

(1) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
(2) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(3) भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन
(4) भारतीय रिजर्व बैंक
(5) प्रश्न का प्रयास नहीं किया गया

विश्लेषण: हालाँकि इस विषय से केवल एक करंट अफेयर्स-आधारित प्रश्न पूछा गया है लेकिन अन्य आर्थिक अवधारणाओं को समझने के लिए भारत के बैंकिंग क्षेत्र की ठोस समझ आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, इस अध्याय से सीधे प्रश्न परीक्षा में आ सकते हैं।

वित्तीय मध्यस्थ

वित्तीय मध्यस्थ वे संस्थाएँ हैं जो वित्तीय प्रणाली में बचतकर्ताओं और उधारकर्ताओं के बीच मध्यस्थ का कार्य करती हैं। ये अतिरिक्त पूंजी वाले लोगों (बचतकर्ता) से पूंजी की आवश्यकता वाले लोगों (उधारकर्ता) तक पूंजी के प्रवाह को संभव बनाती हैं।

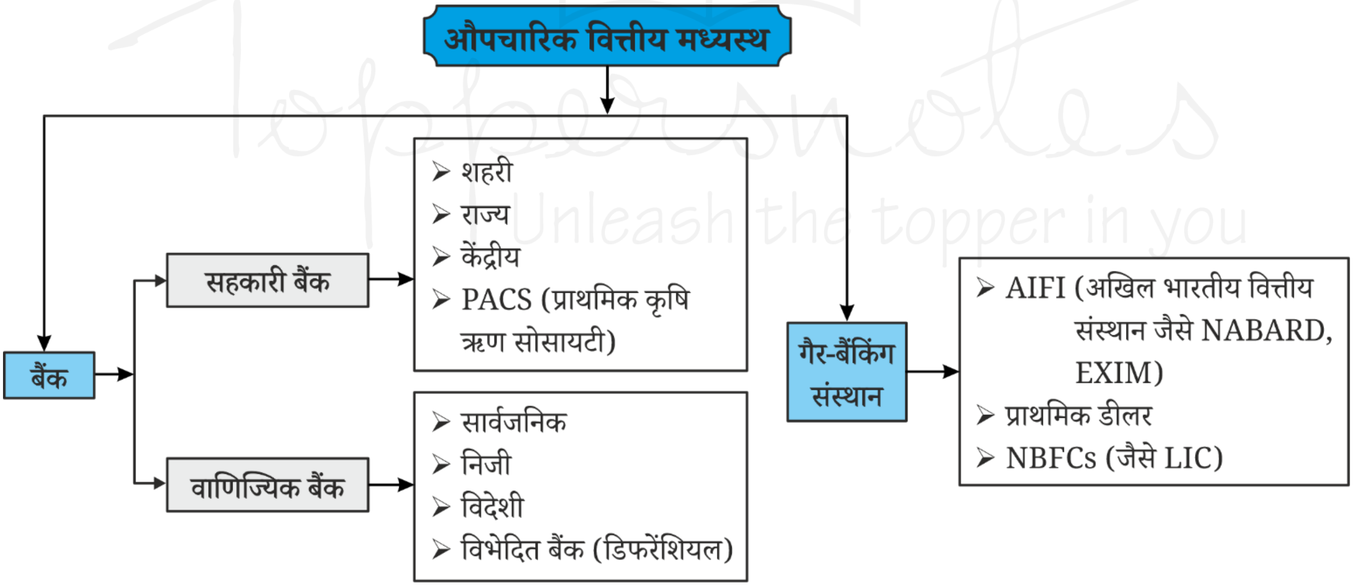
औपचारिक वित्तीय मध्यस्थ
बैंक
सहकारी बैंक
वाणिज्यिक बैंक
➢ शहरी
➢ राज्य
➢ केंद्रीय
➢ PACS (प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटी)
➢ सार्वजनिक
➢ निजी
➢ विदेशी
➢ विभेदित बैंक (डिफरेंशियल)
गैर-बैंकिंग संस्थान
➢ AIFI (अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान जैसे NABARD, EXIM)
➢ प्राथमिक डीलर
➢ NBFCs (जैसे LIC)

बैंकिंग प्रणाली

बैंक एक ऐसी संस्था है जो बुनियादी वित्तीय सेवाएँ प्रदान करती है जैसे जमा स्वीकार करना और ऋण देना।

भारत में बैंकिंग प्रणाली की संरचना

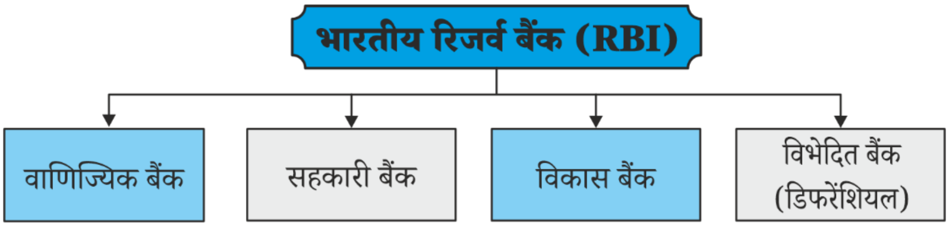
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI)
वाणिज्यिक बैंक
सहकारी बैंक
विकास बैंक
विभेदित बैंक (डिफरेंशियल)

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI)

स्थापना: भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत 1 अप्रैल, 1935 को स्थापित और 1 जनवरी, 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया।

संरचना: गवर्नर + 4 अन्य डिप्टी गवर्नर

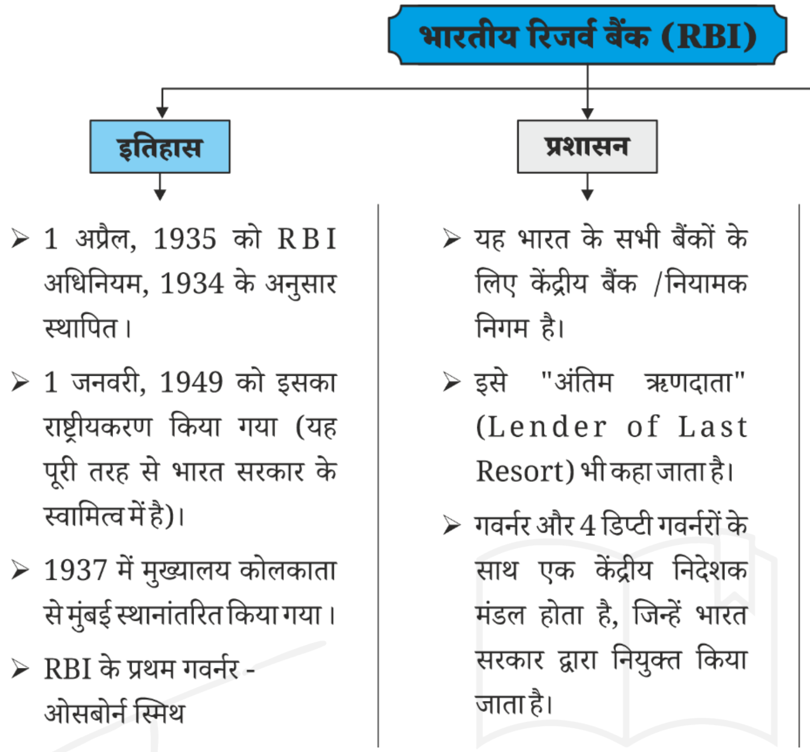

इतिहास

- ➢ 1 अप्रैल, 1935 को RBI अधिनियम, 1934 के अनुसार स्थापित।
- ➢ 1 जनवरी, 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया (यह पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व में है)।
- ➢ 1937 में मुख्यालय कोलकाता से मुंबई स्थानांतरित किया गया।
- ➢ RBI के प्रथम गवर्नर - ओसबोर्न स्मिथ

प्रशासन

- ➢ यह भारत के सभी बैंकों के लिए केंद्रीय बैंक /नियामक निगम है।
- ➢ इसे "अंतिम ऋणदाता" (Lender of Last Resort) भी कहा जाता है।
- ➢ गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नरों के साथ एक केंद्रीय निदेशक मंडल होता है, जिन्हें भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है।

कार्य

- ➢ मुद्रा जारी करती है।
- ➢ सरकार का बैंकर (यह सरकार की ओर से धन की प्राप्ति और भुगतान करती है)।
- ➢ भारतीय बैंकिंग प्रणाली का नियमन करती है।
- ➢ विदेशी मुद्रा संरक्षक
- ➢ ऋण नियंत्रक

मुख्य कार्य:

- ➢ **मौद्रिक प्राधिकरण**: मूल्य स्थिरता बनाए रखने और उत्पादक क्षेत्रों में पर्याप्त धन प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए मौद्रिक नीति का निर्माण और कार्यान्वयन करता है।
- ➢ **मुद्रा जारीकर्ता**: एकमात्र प्राधिकरण है जो एक रुपये के नोट और सिक्कों को छोड़कर,मुद्रा नोट जारी और प्रबंधित करता है| एक रुपये के नोट और सिक्के भारत सरकार द्वारा जारी किए जाते है। यह नकली मुद्रा के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए भी कदम उठाता है।
- ➢ **वित्तीय प्रणाली का नियामक और पर्यवेक्षक**: भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 (पीएसएस अधिनियम) आरबीआई को वित्तीय प्रणाली में स्थिरता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों की निगरानी करने का अधिकार देता है। यह उपकरणों के आदान-प्रदान और भुगतान निर्देशों के प्रसंस्करण की सुविधा प्रदान करता है।
- ➢ **विदेशी मुद्रा प्रबंधन**: विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) का प्रबंधन करता है और बाहरी व्यापार और भुगतान को सुगम बनाता है।
- ➢ अर्थव्यवस्था का नियामक: यह प्रणाली में धन आपूर्ति को नियंत्रित करता है, और जीडीपी, मुद्रास्फीति आदि जैसे प्रमुख संकेतकों की निगरानी करता है।
- ➢ **विकासात्मक भूमिका**: वित्तीय बाजारों के विकास, वित्तीय समावेशन, और भुगतान प्रणालियों को बढ़ावा देता है।
- ➢ **बैंकों का बैंक**: तरलता और सेवाएं प्रदान करके सरकार और अन्य बैंकों के लिए बैंकर की भूमिका निभाता है।
- ➢ बैंकिंग शिकायत निवारण: आरबीआई ने शिकायतकर्ताओं को बैंकों के पुरस्कारों के खिलाफ लोकपाल तक पहुंचने के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए 1995 में बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत की।

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने 17 अगस्त 2023 को UDGAM (अनक्लेम्ड डिपॉज़िट - गेटवे टू एक्सेस इन्फोर्मेशन) पोर्टल लॉन्च किया। यह पोर्टल लोगों को एक ही जगह पर कई बैंकों में पड़े अदावी जमा-सूचना की जानकारी खोजने में मदद करता है।

वाणिज्यिक बैंक

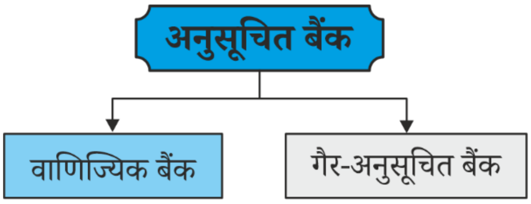

वाणिज्यिक बैंक वे वित्तीय संस्थाएँ हैं जो जमा स्वीकार करने, ऋण देने, और भुगतान लेनदेन को सुविधाजनक बनाने जैसी सेवाएँ प्रदान करती हैं। इन्हें बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत नियंत्रित किया जाता है।

अनुसूचित और गैर-अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के बीच अंतर

अंतर का आधार	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	गैर-अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
अर्थ	RBI अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में सूचीबद्ध।	आरबीआई अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में उल्लेख नहीं किया गया है।
मापदंड	➢ 5 लाख या उससे अधिक की प्रदत्त पूंजी (paid-up capital) होनी चाहिए। ➢ यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके मामलों को उसके जमाकर्ताओं के हितों के लिए हानिकारक तरीके से संचालित नहीं किया जाता है।	➢ ऐसा कोई निश्चित मानदंड नहीं है।
CRR	➢ CRR जमा RBI के पास रखना होगा।	➢ CRR जमा को अपने पास (स्वयं बैंक के पास) रखना होगा।
उपलब्ध अधिकार	➢ RBI से धन उधार लेने के लिए अधिकृत। ➢ क्लियरिंग हाउस में शामिल होने के लिए आवेदन कर सकते हैं। ➢ RBI से प्रथम श्रेणी के विनिमय बिलों पर छूट की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।	➢ आमतौर पर, RBI से धन उधार लेने के लिए अधिकृत नहीं है। हालांकि, ये आपातकालीन परिस्थितियों में RBI से उधार ले सकते हैं। ➢ क्लियरिंग हाउस में सदस्यता के लिए पात्र नहीं है। ➢ RBI से विनिमय बिलों पर छूट की सुविधा के लिए पात्र नहीं है।
उदाहरण	➢ SBI, HDFC Bank	➢ अब तक कोई नहीं

भारत में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के प्रकार –

भारत में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को निम्नलिखित प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

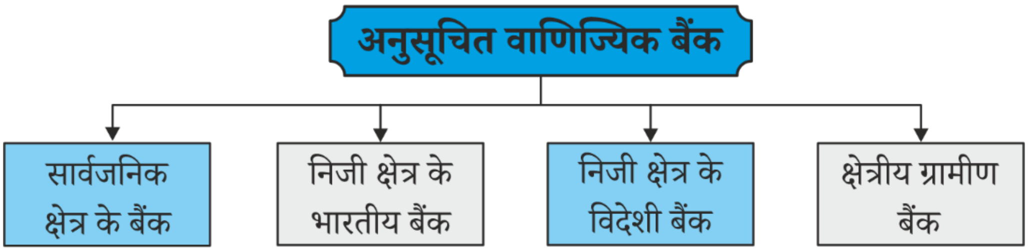
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक
निजी क्षेत्र के भारतीय बैंक
निजी क्षेत्र के विदेशी बैंक
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण

बैंकों का राष्ट्रीयकरण वह प्रक्रिया है जिसमें सरकार निजी बैंकों का नियंत्रण अपने हाथ में लेती है ताकि व्यापक सामाजिक-आर्थिक उद्देश्यों जैसे कि न्यायसंगत ऋण/साख वितरण और वित्तीय समावेशन को हासिल किया जा सके।

समयरेखा:

- 1969: सरकार ने 14 प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया ताकि बैंकिंग ढाँचे और ऋण सुविधाओं का विस्तार किया जा सके, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में।
- 1980: आर्थिक वृद्धि बढ़ाने और बैंकिंग सेवाओं के विस्तार हेतु 6 अतिरिक्त निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया।

प्रभाव:

राष्ट्रीयकरण से बैंकिंग सेवाओं की पहुँच में विशेषकर उपेक्षित और ग्रामीण क्षेत्रों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जिससे वित्तीय समावेशन और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (Public Sector Banks)

- इन्हें राष्ट्रीयकृत बैंक भी कहा जाता है। इन बैंकों में सरकार की बहुमत हिस्सेदारी होती है, यानी 50% से अधिक शेयर सरकार के पास होते हैं।

नोट:–

- पंजाब नेशनल बैंक में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय कर दिया गया है।
- बैंक ऑफ बड़ौदा में देना बैंक और विजया बैंक का विलय कर दिया गया है।

निजी क्षेत्र के बैंक (Private Sector Banks)

- इनमें निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी 51% से अधिक होती है। उदाहरण: ICICI बैंक, Axis बैंक।

विदेशी बैंक (Foreign Banks)

- ये वे बैंक हैं जिनका मुख्यालय किसी अन्य देश में स्थित होता हैं लेकिन भारत में अपनी शाखाएँ संचालित करते हैं। उदाहरण: HSBC, Citibank, Standard Chartered Bank.

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (Regional Rural Banks)

1975 में नरसिम्हन कार्यसमूह की सिफारिशों के आधार पर स्थापित किए गए। इन्हें 1975 के अध्यादेश और 1976 के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम के तहत बनाया गया।

- ✓ **मुख्य ग्राहक**: छोटे और सीमांत किसान, कृषि श्रमिक, ग्रामीण कारीगर और अन्य प्राथमिकता क्षेत्र के ग्राहक।
- ✓ **प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (PSL)**: इन्हें अपने कुल ऋण का 75% प्राथमिकता क्षेत्र को प्रदान करना आवश्यक है।
- ✓ **जमा संग्रहण**: मुख्य रूप से ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों से जमा एकत्र करते हैं।
- ✓ **स्वामित्व**: केंद्रीय सरकार - 50%, राज्य सरकार - 15%, प्रायोजक बैंक - 35%।
- ✓ **नियंत्रण:** RBI द्वारा विनियमित और NABARD द्वारा पर्यवेक्षण।
- ✓ **उदाहरण:** पश्चिम बंगा ग्रामीण बैंक, आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक।